Need to regularize the services of employees working in Regional Rural Banks in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका भी अत्यंत आभारी हूं और संपूर्ण विपक्ष का भी अत्यंत आभारी हूं । संपूर्ण देश से हम जिन अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को इस सदन के माध्यम से उठाएंगे और उनका समाधान होगा । आज हम लोगों का इसका अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो ग्रामीण बैंक्स हैं, सभी राज्यों में उन ग्रामीण बैंकों की लगभग 22,000 शाखाएं हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे पेंशन का विषय हो, किसानों का जन-धन खाता हो, किसान सम्मान निधि हो या छात्राओं की छात्रवृत्ति का पैसा हो, अगर कोई सारे गांवों के लोगों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की सेवा कर रहा है, तो ग्रामीण बैंक्स कर रही हैं । जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनकी तरह उनकी क्रेडिबिलिटी है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे बेहतर सेवाएं कोई और नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग बैंक्स है ।

ग्रामीण बैंकों की अपनी कोई एपेक्स बॉडी नहीं है । आज लगातार एक मांग हो रही है । ये देश की 40 करोड़ जनता की सेवा कर रही हैं । उनकी नेट वैल्यू 50,000 करोड़ रुपये की है तथा आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ रुपये का है । इनमें भारत सरकार का स्वामित्व 50 प्रतिशत है तथा राज्य सरकारों का स्वामित्व 15 प्रतिशत है । जो स्पॉन्शर्ड बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया है, उनका स्वामित्व 35 प्रतिशत है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश में इसका एक रेगुलेशन हो । केन्द्रीय स्तर पर एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे राज्यों में जो अलग-अलग अथॉरिटीज़ हैं, उनका संचालन ठीक ढंग से कर सकें । जब आज इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रही हैं और लाभ दे रही हैं, एनपीए में भी सबसे कम है, इस सरकार की किसानों, नौजवानों तथा महिलाओं के प्रति जो प्राथमिकता है, ये सबसे ज्यादा काम उनके लिए कर रही हैं । इसमें जो खाली पद हैं, उनकी भर्ती भी होनी चाहिए । करीब 20,000 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए । एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (आईएनआरबी) की मांग वर्षों से की जा रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह स्थापित हो । निश्चित तौर से देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों द्वारा जो सेवाओं दी जा रही हैं, उसकी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा ।